

Court No. - 13

Case :-CRIMINAL REVISION DEFECTIVE No. - 475 of 2008

Revisionist :- Razia

Opposite Party :- State of U.P.

Counsel for Revisionist :- Ashok Kumar Srivastava

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Abdul Jabbar

Hon'ble Karunesh Singh Pawar,J.

(C.M. Application No. 83077 of 2008)

1. The application seeks condonation of delay in filing the criminal revision.
2. Heard learned counsel for the revisionist and learned A.G.A. for the State.
3. None appears for respondent no.2.
4. Since cause shown in the affidavit filed in support of application for condonation of delay in filing the instant revision is satisfactory, the application for condonation is allowed and delay in filing the instant revision is hereby condoned.

(Order on the memo of Revision)

1. Heard Shri Avinash Srivastava holding brief of Shri Ashok Kumar Srivastava, learned counsel for the revisionist and learned A.G.A. for the State as well as perused the record.
2. None appears for respondent no.2. However, learned counsel for the revisionist submits that the present revision is pending since 2008 and even objections have not been filed by respondent no.2 and the matter has never been argued by respondent no.2.

3. The present revision has been filed against the judgment and order dated 11.4.2008 passed by learned Additional Sessions Judge, Court No.5, Pratapgarh passed in Criminal Revision No.54 of 2007, whereby the order of trial Court dated 23.1.2007 has been modified. The maintenance allowance of Rs.1000/-awarded in favour of the revisionist no.1 has been canceled or set aside and maintenance allowance in favour of revisionist nos. 2 and 3 has been reduced to Rs.250/- per month from Rs.500/- per month each.

4. Learned counsel for the revisionist submits that learned trial Court vide judgement and order dated 23.1.2007 has allowed the application under Section 125 Cr.P.C. filed by the revisionist after adjudicating five issues. All those issues have been decided in favour of the revisionist. Aggrieved by the order passed by the trial Court, respondent no.2 filed the revision before the revisional court, wherein the impugned order dated 11.4.2008 has been passed.

5. Submission of learned counsel for the revisionist is that the revisional Court has wrongly relied and misinterpreted the judgment of **Danial Latifi and another vs. Union of India** reported in AIR 2001 SC 3958 by allowing the revision. He submits that revision has been allowed only on the ground that since the revisionist no.1 has been divorced by respondent no.2 both are governed by The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 and therefore in view of judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Danial Latifi (supra), after enforcement of this Act, the divorced Muslim women is entitled to get maintenance under Section 3 and Section 4 of

the aforesaid Act even after the stage of *iddat* and therefore she is not entitled to receive maintenance under Section 125 Cr.P.C. In support of his arguments, he has relied on the judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of **Shabana Bano vs. Imran Khan** passed in Criminal Appeal No.2309 of 2009.

6. Learned counsel for the revisionist submits that till date not a single penny has been given by respondent no.2 to the revisionist.

7. On due consideration and perusal of the record as well as the impugned judgment passed by the trial court, it is not in dispute that respondent no.2 is a person of having sufficient means to maintain his divorced wife and minor children. Issue no.1 has been decided by learned trial Court in favour of the revisionist. Likewise he has neglected to maintain his wife and minor children. The revisionist is destitute and have no source of income and revisionist is entitled to get the maintenance allowance from respondent no.2 and consequently issue nos. 2 to 5 have been decided in favour of the claimant revisionist.

8. It appears that revisional court has modified the order passed by the learned trial court and maintenance allowance granted under Section 125 Cr.P.C. in favour of respondent no.1 has been set aside and the allowance granted in favour of respondent nos.2 and 3 have been reduced to Rs. 250/- from Rs. 500/- per month.

9. From perusal of the impugned order, it appears that the finding of fact regarding the monthly income of the respondent no.2 given by the learned trial Court has been substituted by the revisional Court by

its own finding and a different finding, which, in my opinion, is not permissible, while exercising jurisdiction in the criminal revision. On this ground, the maintenance allowance awarded to the revisionists no.2 and 3 has been reduced to half, which is also not proper.

10. Learned revisional Court, while setting aside the maintenance allowance granted in favour of the revisionist no.1 by the trial court, has relied on the judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Danial Latifi (Supra). The finding given by learned revisional Court is extracted below:-

तलाक के बिन्दु पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से काफी बहस की गयी है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि तलाकशुदा पत्नी किसी भी रूप में धारा 125 द०प्र०सं० के अन्तर्गत गुजारा भत्ता पाने को अधिकारिणी नहीं है। इस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन आफ राइट आन डाइवोर्स एक्ट 1986 की धारा 03 तथा धारा 04 के प्रावधानों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया। धारा 03 में यह कहा गया है कि जब मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तब वह मैहर तथा अन्य सम्पत्तियाँ पाने की अधिकारिणी होती है तलाक के समय पहले पति से यह इद्दत के पीरियड के अन्दर रिजनेबुल तथा पेपर एंव निर्वाह भत्ता पाने की अधिकारिणी होती है। यह सामान पहले वाले पति द्वारा वापस दिया जाता है। इसी प्रकार से धारा 04 में यह कहा गया है कि अपने पति से यदि यह निर्वाह भत्ता पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है तो उसका निर्वाह भत्ता रिश्तेदार देंगे। यदि वह लोग भी देने में सक्षम न हो तब मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत राज्य वक्फ बोर्ड को आदेश दे सकता है कि तलाकशुदा पत्नी का निर्वाह भत्ता दिया जाय। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से नजोर 2001 वॉलूम 45 ए०एल०आर० पेज 426 डेनियल लतीफी आदि बनाम यूनियन आफ इंडिया दाखिल किया है यह नजीर माननीय उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायमूर्ति गण के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि एक मुस्लिम औरत अपने पति के द्वारा तलाक पा लेती है और वह 125 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत निर्वाह

भत्ता उस पति से प्राप्त कर लेती है तो यदि यह अधिकार समाप्त कर दिया जो रिजनेबुल जस्ट तथा पेपर न होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने का तात्पर्य है कि अधिनियम की धारा 09 व 04 के अन्तर्गत पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिये कुछ न कुछ निर्वाहन के लिये करना होगा। यह केवल इदत्त के समय को अवधि तक के लिये सीमित नहीं है । मुस्लिम तलाकशुदा औरत अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है कि यदि वे रिश्तेदार निर्वाह भत्ता देने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट स्टेट वक्फ बोर्ड को आदेश निर्वाह भत्ता के लिये जारी कर सकता है। इस नजीर के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि तलाक शुदा पत्नी अपने पूर्व पति से निर्वाह भत्ता पाने की अधिकारिणी नहीं है ।

तलाक से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख पहले आ चुका है। कि निगरानीकर्ता ने पहली बार तलाक को बात अपने जबाब दावे में नहीं कही बल्कि साक्षी नासिर अली जो निगरानीकर्ता की ओर से साक्षों के रूप में प्रस्तुत हुआ है उसने कहा है कि पक्षकारों के मध्य पहले तलाक हो तलाक का चुका था। तलाक के समय रजिया उस समय नकाब में नहीं थी तलाक जुबानी हुआ था। तलाक में लिखापढ़ी नहीं हुई थी। इस साक्षी के कथनानुसार तलाक के समय रजिया उपस्थिती यह तिथि 16.10.99 की थी जिस दिन रजिया के उपेक्षा एवं तिरस्कृत पूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर जैनुद्वोन को तलाक देने की आवश्यकता हुई । इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य तलाक वैध रूप से प्रभावी है। इस तलाक के लिये रजिया को ही दोषी ठहराया जायेगा जैनुद्दीन को नहीं क्योंकि रजिया ही स्वेच्छा से मायके में रह रही है। निगरानीकर्ता के द्वारा दाखिल उपरोक्त नजीर के अवलोक्त से स्पष्ट है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला थारा 125 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत पूर्व पति से जिसने मेहर तथा इदत्त की अवधि की पूरा पैसा अदा कर दिया है निर्वाह भत्ता पाने को अधिकारिणी नहीं है । मौजूदा केस में यही है कि निगरानीकर्ता ने रजिया को तलाक दे दिया है जिसके फस्वरूप रजिया निर्वाह भत्ता धारा 125 फौजदारी के अन्तर्गत पाने को अधिकारिणी नहीं है। निगरानीकर्ता यह स्वीकार करता है कि अपने दोनों बच्चों को निर्वाह भत्ता देने को तैयार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी कर्ता की आय को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक निर्वाह भत्ता की धनराशि प्रदान करने का आदेश पारित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिजनेबुल एण्ड पेपर का सिद्दन्त है कि वह धारा 03 मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन आफ राइट आफडाइवोट एक्ट 1986 के अन्तर्गत पारित किया गया है। धारा 125, के प्राध्यान इस एक्ट के लागू हो जाने से मुस्लिम तलाकशुदा महिला का कोई वास्ता सरोकार नहीं रह जाता है। उक्त एक्ट की धारा 30 व 04 के अन्तर्गत वह इदरत की अवधि के पश्चात भी निर्वाह भत्ता अपने पूर्व पति से पा सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विपक्षी संख्या 01 रजिया धारा 125 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता पाने को अधिकारी नहीं है। विपक्षी संख्या 2 व 3 निगरानीकर्ता से निर्वाह पाने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ PRITI निर्वाह भत्ता की धनराशि 500/= 500/- रुपये प्रदान के लिए आदेश पारित किया है वह इसलिए जो तर्कसंगत नहीं है कि निगरानीकर्ता को आय का एक मात्र साधन उसको वेतन है यह वेतन 1500/= रुपये प्रतिमाह है जिसे विपक्षी ने भी स्वीकार किया है। ऐसी दशा में विपक्षी सं० 2 व 3 के निर्वाह भत्ता की धनराशि पांच सौ रुपये से घटाकर 250/= 250/= रुपये निर्धारित किया जाना उचित एवं तर्क संगत प्रतीत होता है। फलस्वरूप निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 23-01-2007 संशोधित किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 के हक में निर्वाह भत्ता की धनराशि 1000/- रुपये समाप्त की जाती है विपक्षी 2 व 3 के हक में निर्वाह भत्ता दिये जाने की न्यून धाराशि 500/-, 500/- रुपये से कम करके 250/= दो सौ पचास रुपये दिये जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है। पक्षकार वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजी जाय ।

11. Hon'ble Supreme Court in the case of **Sabana Bano (Supra)** has held that a divorced Muslim women can be entitled for divorce as long as she does not re-marry. Further, it has been held that provision under Section 125 Cr.P.C. are beneficial piece of legislation and the

benefit thereof must accrue to the divorced Muslim women. It has also been held that the divorced Muslim women shall be entitled to claim maintenance from her husband under Section 125 Cr.P.C. even after expiry of period of *iddat* as long as she does not remarry. Relevant paragraphs 29 and 30 of the judgment are extracted below:-

" 29. Cumulative reading of the relevant portions of judgments of this Court in Danial Latifi (supra) and Iqbal Bano (supra) would make it crystal clear that even a divorced Muslim woman would be entitled to claim maintenance from her divorced husband, as long as she does not remarry. This being a beneficial piece of legislation, the benefit thereof must accrue to the divorced Muslim women.

30. In the light of the aforesaid discussion, the impugned orders are hereby set aside and quashed. It is held that even if a Muslim woman has been divorced, she would be entitled to claim maintenance from her husband under Section 125 of the Cr.P.C. after the expiry of period of iddat also, as long as she does not remarry."

12. In view of the aforesaid judgement of **Sabana Bano (Supra)**, I have no hesitation in holding that the view taken by the revisional Court is contrary to the law laid down by Hon'ble Supreme Court. The revisionist no.1 being a divorced Muslim women was entitled to claim maintenance under Section 125 Cr.P.C. There is no illegality in the order passed by the trial Court.

13. Accordingly, the impugned order passed by the learned revisional Court is set-aside in view of law laid down by Hon'ble Supreme Court in the case **Sabana Bano (supra)**.

14. While passing the judgment, this Court has noticed that the maintenance has been awarded to the revisionist under Section 125 Cr.P.C. from the date of the order, which according to recent judgment

of Hon'ble Supreme Court in Rajnesh vs. Neha and another reported in (2021) 2 SCC 324, should be paid from the date of application filed under Section 125 Cr.P.C. and therefore, judgment being retrospective in nature is applicable in present case.

15. Hence, the order passed by the learned trial court dated 23.1.2007 is also modified to the extent that the revisionist shall be paid maintenance by respondent no.2 from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C. Any amount already paid during the pendency of the proceedings under Section 125 Cr.P.C. by respondent no.2 shall be adjusted.

16. The present revision is, accordingly, **allowed**.

Order Date :-6.4.2022

Madhu